



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2018/फाल्गुन 1, 1939

No. 65]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2018/PHALGUNA 1, 1939

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

(प्रधान कार्यालय, गुरुग्राम)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 24 जनवरी, 2018

एफ नं. 3950.—बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण), 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का बैंक ऑफ़ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

- (1) यह विनियम ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहे जाएंगे।
(2) जब तक इन विनियमों में अन्यथा उल्लेख न हो, ये नवम्बर, 2007 की पहली तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।
- ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में (जिसे आगे उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 3 में, -

(i) खण्ड (च) के लिए निम्नलिखित खण्ड स्थानापन्न किए जाएंगे, यथा:-

‘(च) “परिवार” का तात्पर्य है अधिकारी की पत्नी / पति, पूर्णतः निर्भर अविवाहित बच्चे (सौतेले एवं विधिक रूप से गोद लिए गए बच्चे सहित), चालीस प्रतिशत अथवा अधिक के दिव्यांग भाई अथवा बहिन और सामान्यतः साथ रहने वाले एवं अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता’.

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए बच्चे अथवा माता-पिता अथवा दिव्यांग भाई अथवा बहिन उस स्थिति में अधिकारी पर आश्रित माने जाएंगे जबकि ऐसे बच्चे, माता-पिता, भाई अथवा बहिन की मासिक आय रु.3500/- से अधिक न हो।

बशर्ते, माता अथवा पिता की मासिक आय रु.3500/- से अधिक अथवा माता-पिता की कुल मासिक आय रु.3500/- से अधिक हो तो माता एवं पिता दोनों अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माने जाएंगे।’

(ii) खण्ड (ण) को हटा दिया जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में,-

(i) उप-विनियम (4क) को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4क) को हटाने के बाद निम्न उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(5) 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी, प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वेतनमान निम्नानुसार होंगे :

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = रु. 46800 – 1300/4 – 52000

वेतनमान VI = रु. 42000 – 1200/4 – 46800

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = रु. 36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 – 40400

वेतनमान IV = रु. 30600 – 900/4 – 34200 – 1000/2 – 36200

(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = रु. 25700 – 800/5 – 29700 – 900/2 – 31500

वेतनमान II = रु. 19400 – 700/1 – 20100 – 800/10 – 28100

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = रु. 14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

स्पष्टीकरण- प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्तूबर, 2007 को प्रभावी वेतनमान से शासित है, को स्टेज-दर-स्टेज आधार पर 1 नवंबर, 2007 को इस उप-विनियम में व्यवस्थित वेतनमान में नियतन किया जाएगा अर्थात् संबंधित वेतनमान में प्रथम स्टेज से तदनुरूपी स्टेजों पर तथा वेतनवृद्धि वार्षिक तिथि पर सामान्य रूप से देय होगी, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) एवं (5) की किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि बैंक के लिए सदैव इन सभी श्रेणियों में अधिकारियों को रखना अपेक्षित है।”.

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में, -

(क) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, 1 नवंबर, 2007 को एवं इसके बाद से वेतनवृद्धि को निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाएगा, नामतः :-

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में व्यवस्थित वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन वार्षिक आधार पर देय होगी तथा जिस माह में देय होगी उसकी पहली तारीख को जारी की जाएगी;

(ख) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में ऐसे अधिकारी जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के वेतनमान में पहुंच चुके हैं, अपने सेवाकाल के प्रत्येक पूर्ण तीन वर्षों के लिए चार गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनमें से पहली दो प्रत्येक रु.800/- की तथा आगामी दो प्रत्येक रु.900/- की होंगी;

बशर्ते, ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1 नवंबर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष या अधिक पूरे कर लिए हों 1 नवंबर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे तथा दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के छह वर्ष पूरे कर लेने के बाद 01 नवंबर, 2008 को अथवा इसके बाद अन्य गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे ;

(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में ऐसे अधिकारी जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने पर मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के वेतनमान में पहुँच चुके हैं, अपने सेवाकाल के प्रत्येक पूर्ण तीन वर्षों के लिए प्रत्येक रु. 900/- के तीन गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे:

बशर्ते ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1 नवंबर, 2007 को पहली गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, को 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी आगामी वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे तथा पहली गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के छह वर्ष पूर्ण होने पर 1 नवंबर, 2008 को अथवा इसके बाद उत्तरवर्ती गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे:

बशर्ते, यह भी कि मुख्यतः मध्यम प्रबंधन श्रेणी III में नियुक्त अथवा पदोन्नत अधिकारी सेवाकाल के प्रत्येक पूर्ण तीन वर्षों के लिए प्रत्येक रु. 900/- की चार गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे अथवा:

बशर्ते, यह भी कि ऐसे सभी अधिकारी जिन्होंने पहले ही दो गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त कर ली हैं तथा 1 नवंबर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण कर ली हो, 01 नवंबर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे तथा दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने के छह वर्ष के बाद 1 नवंबर, 2008 को अथवा इसके बाद चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे

परन्तु अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि(यां)/ अवरोध वेतनवृद्धि(यां) उस अधिकारी को नहीं दी जाएंगी, जिसने पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर दिया हो।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के अंतर्गत इस प्रकार की वेतनवृद्धि जारी किए जाने का अर्थ अधिकारी की पदोन्नति नहीं है तथा ये अधिकारी अपने मूल पद के अनुरूप सुविधाएं, परिलब्धियां, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का वहन करते रहेंगे।

(ख) उप-विनियम (2) में,-

(i) स्पष्टीकरण में, खण्ड (ड.) के बाद तथा टिप्पणी से पहले निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(च) 1 नवंबर, 2007 को तथा उसके बाद से अन्य बातों के समान रहने पर व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

सारणी

जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट अथवा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है	(i) उच्चतम वेतनमान में पहुँचने के एक वर्ष बाद से रु. 410 प्रति माह
जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(i) उच्चतम वेतनमान में पहुँचने के एक वर्ष बाद से रु. 410 प्रति माह (ii) उच्चतम वेतनमान में पहुँचने के दो वर्ष बाद से रु. 1030 प्रति माह

बशर्ते, यदि किसी अधिकारी जिसने उच्चतम वेतनमान में पहुँचने के बाद भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट अथवा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (कोई एक अथवा दोनों भाग) की अर्हता प्राप्त की हो, उन्हें यह अर्हता प्राप्त करने की तिथि से व्यावसायिक योग्यता वेतन की प्रथम किश्त का भुगतान किया जाएगा और उसके बाद के व्यावसायिक योग्यता वेतन की किश्तों का निस्तारण व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किश्त के भुगतान की तिथि के अनुरूप ही किया जाएगा।

इसके अलावा यदि किसी अधिकारी ने उपरोक्त में से कोई भी अर्हता पहले ही प्राप्त कर ली है और इसके एवज में उसे किसी प्रकार की वेतन-वृद्धि अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे मामले में उसे व्यावसायिक योग्यता वेतन का भुगतान 1 नवंबर, 2007 अथवा ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि में से जो भी बाद में हो, से किया जाएगा।

(ii) टिप्पणी में, खंड (v), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(v) यदि किसी अधिकारी ने 27 अप्रैल 2010 तक खंड (iv) में वर्णित उपरोक्त में से कोई भी अर्हता प्राप्त कर ली है और इसके एवज में उसे किसी प्रकार की वेतन-वृद्धि अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे मामले में उसे व्यावसायिक योग्यता वेतन का भुगतान 1 नवंबर 2007 से अथवा ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि, में से जो भी बाद में हो, से किया जाएगा।”

(ग) उप विनियम (3) में,-

(i) खंड (घ) के बाद एवं टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड को इसमें प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा

“(ड) 1 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर, नियत वैयक्तिक वेतन के साथ मकान किराया भत्ता निम्नलिखित दर के अनुसार होगा और पूरे सेवाकाल के लिए यह स्थिर रहेगा :-

सारणी		
वेतन वृद्धि घटक (रु.)	वेतन वृद्धि घटक पर 01.11.2007 को महंगाई भत्ता (रु.)	बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराने के मामले में देय कुल नियत वैयक्तिक वेतन (रु.)
(क)	(ख)	(ग)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394

(ii) टिप्पणी में, खंड (i) और (ii), के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(i) सारणी के खंड (ख), (ग), (घ) अथवा (ड) के तहत सारणी के कॉलम (ग) में वर्णित नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन का भुगतान उन अधिकारियों को किया जाएगा जिन्हें बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) मकान किराया भत्ते हेतु पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन, खंड (ड) के तहत सारणी के कॉलम (क) और (ख) में निर्दिष्ट राशि तथा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4) अथवा (5) में यथा निर्दिष्ट संबन्धित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त किए जाने पर संबन्धित अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जा रहे मकान किराया भत्ते की कुल समेकित राशि होगी।

(iii) टिप्पणी के बाद आने वाले खंड (ड) को अब से उप-खंड (v) के रूप में अंकित किया जाएगा और खंड (v) की जगह निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(v) ऐसा अधिकारी जिसने उपरोक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त की है, अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के एक वर्ष बाद उपरोक्त खंड (ख), (ग), (घ) या (ड) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते/ नियत वैयक्तिक वेतन की राशि प्राप्त करेगा।”

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में :-

(i) उप-विनियम (3) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम एवं टिप्पणी शामिल किए जाएंगे, यथा:-

“(5) 1 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, महंगाई भत्ता, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार, 1960=100 पर वेतन के 0.15% पर तिमाही औसत में 2836 अंकों के ऊपर हर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट हेतु देय होगा,

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के उद्देश्य हेतु-

(क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु “वेतन” से तात्पर्य अवरुद्ध वेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन होगा।

(ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ), (ङ) एवं (च) में यथा वर्णित व्यावसायिक योग्यता भत्ता अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन की गणना, महंगाई भत्ते के लिए की जाएगी।

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियमों (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

“(1) 1 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से ,

(क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गयी है, तो उसे प्रदत्त वेतनमान के प्रथम चरण, के मूल वेतन के 1.75% के समतुल्य राशि अथवा आवास का मानक किराया, जो भी कम हो उससे वसूला जाएगा।

(ख) जहां किसी अधिकारी कर्मचारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गयी है, तो वह निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा, यथा:-

सारणी

कार्यस्थल निम्नलिखित क्षेत्रों में होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख “ए” श्रेणी के शहर एवं समूह “ए” में परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र-I में अन्य स्थान एवं समूह “बी” में परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

बशर्ते यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे प्रदत्त वेतनमान के प्रथम चरण के वेतन के 1.75% के अलावा आवासीय सुविधा हेतु उसके द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराये के लिए उसे मकान किराया भत्ता देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा उपरोक्त सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट मकान किराया भत्ते के 150% तक होगी।

(2) 1 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, -

(क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गयी है, वहाँ उसे प्रदत्त वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.20% के समतुल्य राशि अथवा आवास का मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूला जाएगा।

(ख) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गयी है, उस स्थिति में वह निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा, यथा:-

सारणी

कार्यस्थल निम्नलिखित क्षेत्रों में होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर तथा समूह "ए" में परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 8.5%
(ii) एरिया 1 के अन्य शहर तथा समूह बी में परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ते का भुगतान उसके द्वारा आवास हेतु भुगतान किए गए वास्तविक किराये के रूप में किया जाएगा जो कि वेतनमान के पहले चरण के वेतन के 1.20% से अधिक होगा जो उपर्युक्त कॉलम(2) में वर्णित उपरोक्त दरों के अनुसार उसके मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा।

टिप्पणी - मकान किराया भत्ते के लिए अधिकारियों के दावे, जो उनके स्वामित्व वाले आवास की लागत से सम्बद्ध है, को भी अब से मकान किराया भत्ते के 150 % तक सीमित रखा जाएगा।";

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,-

- (i) उप-विनियमन (1) में, अंक, अक्षर, एवं शब्द "नवंबर, 2002 का पहला दिन" के लिए, "नवंबर, 2007 का पहला दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-विनियम (2) में, अंक, अक्षर एवं शब्द "नवंबर, 2002 का पहला दिन" के लिए, "नवंबर, 2007 का पहला दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) उप-विनियम (3), (4) एवं (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-
 "(3) 1 नवंबर, 2007 को तथा उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी समूह ए एवं बी में आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो वह समूह ए या समूह बी के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र के अनुसार रु. 290 प्रति माह अथवा रु. 225 प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

(4) 1 नवंबर, 2007 को तथा उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तथा उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान के विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो वह नए स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक अपने सभी बच्चों के लिए रु.700 प्रति माह शैक्षणिक वर्ष के मध्य स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा, परंतु यदि उसके सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर दें तो उस दशा में ऐसा भत्ता समाप्त हो जायेगा।

(5) 1 मई, 2010 को तथा उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो, वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियाँ प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, अथवा वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु. 2300 प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं ऐसे अन्य भत्ते जो कि वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थ होने पर लेता, ले सकता है:

परंतु यदि वह ऐसे प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्त हुआ है जो उसी स्थान पर है जहाँ पर वह प्रतिनियुक्ति के ठीक पहले पदस्थापित था, तो वह अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा जो अधिकतम रु.1200 प्रति माह होगा:

परंतु यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कोई अधिकारी अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.1200 प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।"

- (iv) उप-विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(8) 1 नवंबर, 2007 को तथा उसके बाद से, यदि एक दिन के दौरान कार्य-समय को दो घंटे के न्यूनतम अंतराल में विभाजित किया जाता है तो अधिकारी रु.165 प्रति माह की दर से विभाजित ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।";

(v) उप-विनियम (10) में,-

(क) अंक, अक्षर, एवं शब्द "नवंबर, 2002 का पहला दिन" के लिए, "नवंबर, 2007 का पहला दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी के लिए, निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“सारणी

स्थान (1)	दर (2)
(i) 1000 मीटर एवं उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई वाले स्थान एवं मरकारा टाऊन	वेतन का 2% परंतु अधिकतम रु. 550 प्रति माह।
(ii) 1500 मीटर एवं अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान।	वेतन का 2½% परंतु अधिकतम रु. 680 प्रति माह।
(iii) 3000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% परंतु अधिकतम रु. 1570 प्रति माह।”;

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 के उप-विनियम (1) में, खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(क) चिकित्सा व्यय. - 01 नवंबर, 2007 को तथा उसके बाद से, कोई अधिकारी नीचे दी गयी सारणी में यथाविनिर्दिष्ट दावाकृत राशि के लिए दिए गए विवरण द्वारा समर्थित इस प्रकार के व्यय को करने से संबन्धित अधिकारी के स्वयं के प्रमाणपत्र के आधार पर स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा, यथा:-

सारणी

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन एवं मध्यम प्रबंधन श्रेणी	रु. 5100 अथवा व्यय राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन एवं शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु. 6320 अथवा व्यय राशि, जो भी कम हो

टिप्पणी.- (i) किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता राशि को संचित करने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु वह किसी भी समय ऊपर उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी अथवा;

(ii) वर्ष 2007 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने अर्थात्, नवंबर 2007 और दिसंबर 2007 के लिए यथानुपात बढ़ाई जाएगी।

(ख) अस्पतालीकरण व्यय:

(i) अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी मामलों के संबंध में अधिकारी के मामले में 100 प्रतिशत एवं उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75 प्रतिशत तक अस्पतालीकरण के प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) 01 मई, 2010 को या उसके बाद से, इस विनियम के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती की प्रतिपूर्ति, कामगार कर्मचारियों के लिए दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत निर्धारित अस्पतालीकरण योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार, नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट सीमाओं के अध्येधीन होगी, अर्थात्:

सारणी

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III.	<p>(i) बेड चार्जेंस स्वयं – रु. 700 प्रति दिन परिवार – रु. 525 प्रति दिन</p> <p>(ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पतालीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 125% की दर पर।</p>
(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV एवं V तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII.	<p>(i) बेड चार्जेंस स्वयं – रु. 900 प्रति दिन परिवार – रु. 675 प्रति दिन</p> <p>(ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पतालीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 150% की दर पर</p>

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा –
- "(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुये भी, 1 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के समतुल्य राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, भुगतान जाने पर बैंक किसी अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा:
- परंतु, जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्निचर उपलब्ध कराया गया हो, वहाँ बैंक द्वारा उससे उस वेतन के वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के प्रथम चरण के, मूल वेतन के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त राशि भी वसूली जाएगी:
- परंतु यह भी कि, जहां बैंक द्वारा ऐसी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई व्यवस्था के लिए प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे;"
10. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम को जोड़ा जाएगा, यथा –
- "(3) 1 मई, 2010 से 12 महीने की समग्र अवधि के भीतर, हिस्टेरेक्टोमी के मामले में अधिकतम 45 दिनों तक अवकाश भी दिया जा सकेगा।"
11. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-
- '(क) विराम भत्ता – 1 मई, 2010 को और उसके बाद से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में निर्धारित श्रेणियों या वेतनमानों में अधिकारी कॉलम (2) में निर्धारित की गई दरों पर प्रति दिन विराम भत्ता का हकदार होगा, यथा:-

सारणी

अधिकारियों के श्रेणी/वेतनमान	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
वेतनमान IV एवं उससे ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	800	700	600

परंतु वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में कार्यालय से बाहर किसी कार्य हेतु देय दैनिक विराम भत्ता रु.1200 होगा और वेतनमान I या II या III के अधिकारियों के लिए दैनिक विराम भत्ता रु. 1000 होगा।

परंतु यह भी कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक है, विराम भत्ता उपरोक्त दरों से आधी दरों पर देय होगा।

स्पष्टीकरण- विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए 'प्रति दिन' का तात्पर्य चौबीस घंटे या उसके बाद के किसी भाग की प्रत्येक अवधि से होगा, हवाई यात्रा की स्थिति में जिसकी गणना प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहाँ "प्रति दिन" से तात्पर्य कम से कम आठ घंटे की अवधि अभिप्रेत होगी।

12. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, यथा -

“(4) 1 मई, 2010 को या उसके बाद से, स्थानांतरण पर अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से संबंधित खर्चों के लिए निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट एकमुश्त राशि प्राप्त करने का पात्र होगा, अर्थात् :-

सारणी

श्रेणी	एकमुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 12,000
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 9,000”.

13. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) में, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, यथा:-

“परंतु 1 मई 2010 से, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी, छुट्टी किराया रियायत का उपभोग करते समय न्यूनतम किराया वाली इकॉनोमी क्लास में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा, इस मामले में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया अथवा तय की गई दूरी के लिए रेल की एसी प्रथम श्रेणी का किराया, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी एवं यही नियम मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के किसी अधिकारी के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय लागू होगा, जहां दूरी 1000 किमी से कम है।”

14. उक्त विनियमों के विनियम 45 में, -

(i) उप-विनियमन (1) में, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“परंतु 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में कार्य ग्रहण करने वाले अधिकारियों के लिए भविष्य निधि नहीं होगी।”

(ii) उप-विनियमन (3) में, खंड (ख) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, यथा :-

“(ग) अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल अधिकारी जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं दिया है, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत बने रहेंगे।

(iii) उप-विनियमन (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किया जाएगा, यथा :-

“(4) 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद से बैंक की सेवा में कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल होंगे, जहां अधिकारी 10 प्रतिशत वेतन और महंगाई भत्ते का अंशदान करेगा और भारत सरकार की अधिसूचना, एफ़ नं.5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003, समय-समय पर यथासंशोधित, के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के अनुसार, अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार बैंक योगदान की समान राशि का अंशदान करेगा।

15. उक्त विनियमों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित होगी, अर्थात्:-

“(अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 की अनुसूची

[विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें]

1 नवंबर, 2007 से, निम्न सारणी में यथानिर्दिष्ट, कोई अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि उन्हें पूर्णतया या अंशतः हटाया या संशोधित नहीं किया जाता है, यथा :-

तालिका

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		रु.14,700/- से कम वेतन	रु.14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
1.	मिज़ोरम (क) मिज़ोरम का चिम्पतुपुई जिला तथा मिज़ोरम के लुंगली जिले में लुंगली शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्र (ख) मिज़ोरम के लुंगली शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त लुंगली जिला (ग) मिज़ोरम का समस्त आइजोल जिला	2000 1600 1200	2600 2100 1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह (क) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार तथा नारकोंदम द्वीप समूह (ख) दक्षिण अंडमान (पोर्टब्लेयर सहित)	2000 1600	2600 2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	2000	2600

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		रु.14,700/- से कम वेतन	रु.14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा (क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र (ख) दुर्गम क्षेत्र के अतिरिक्त समस्त त्रिपुरा	1600 1200	2100 1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश (क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र (ख) दुर्गम क्षेत्र के अतिरिक्त समस्त अरुणाचल प्रदेश	2000 1600	2600 2100
11.	जम्मू एवं काश्मीर (क) कटुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मलहार तथा मझोदी	2000	2600
	(ख) उधमपुर जिला: (i) डुडू बसंतगढ़, लेंडर भामग इलाका, खंड ख (ii) में सम्मिलित के अतिरिक्त अन्य (ii) कमबन की तरफ से गुल तक के क्षेत्र तथा तहसील मोढ़ में केसई की तरफ से अरनास तक के क्षेत्र	2000 1600	2600 2100
	(ग) डोडा जिला: किशतवार तहसील में पेडुर और नियाबत नौगाम के इलाके (घ) लेह जिला : जिले के सभी क्षेत्र (ड.) बारामूला जिला (i) संपूर्ण गुरेज़-निराबत, तंगदार उप-खंड तथा करण इलाका (ii) मच्छिल (च) पुंछ और राजौरी जिला : पुंछ तथा राजौरी और सुंदरबानी एवं दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र (छ) क्षेत्र जो उक्त (क) से (च) तक की मदों में सम्मिलित नहीं हैं, परंतु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किमी के भीतर हैं या ऐसे स्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने स्टाफ के लिए सीमा भत्ता दिये जाने हेतु पात्र घोषित किया जाए।	2000 2000 2000 1600 1200 1200	2600 2600 2600 2100 1500 1500
12.	हिमाचल प्रदेश (क) चम्बा जिला (i) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें : बड़गांव, बाज़ोल, देवल कुगटी, नयागाम तथा टुंडा, गाँव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा का कनारसी	2000	2600

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		रु.14,700/- से कम वेतन	रु.14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
	(ii), उक्त मद (i) में सम्मिलित पंचायतों एवं ग्रामों के अतिरिक्त, भरमौर तहसील	1600	2100
	(iii) भटीयट तहसील में झांडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौज़ी टाउन (बानीखेत सहित)	1200	1500
	(ख) किन्नौर जिला : (i) असरंग, चिटकुल तथा हंगो कुनो/चरांग पंचायतें, छोटा कांबा, नाथपा तथा रूपी, पूह उप-खंड की ग्राम पंचायतों वाले 15/20 क्षेत्र, ऊपर विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों के अतिरिक्त। (ii) उक्त (i) में सम्मिलित क्षेत्रों के अतिरिक्त पूरा जिला	2000 1600	2600 2100
	(ग) कुल्लू जिला : (i) खारगा, कुशवार तथा सरगा की ग्राम पंचायतों सहित निर्मांड तहसील के 15/20 क्षेत्र (ii) बाहरी-सराज (निर्मांड तहसील में जकात-खाना और बुरों के गांवों के अतिरिक्त) तथा बाहरी सेराज क्षेत्र एवं पंद्राबीस के परगना के अतिरिक्त और तहसील निरमंद के गांव जगत-खाना तथा बुरों सहित संपूर्ण जिला।	2000 1200	2600 1500
	(घ) लाहौल और स्पीति जिला : लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	2000	2600
	(ङ.) शिमला जिला : (i) कूट, लबाना-सदाना, सरपारा तथा चड़ी-ब्रांडा की पंचायतों वाली रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र।	2000	2600
	(ii) डोरा – कवर तहसील, रामपुर में डरकाली ग्राम पंचायत, तहसील काशपथ तथा मुनीश, परगना सराहन की घोरी चौबीस। (iii) चौपाल तहसील तथा घोरीस, पंजगांव, पत्सनाऊ, नौबीस तथा परगना सराहन की तीन कोटी, ताकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, परगना बाराबीस, कसबा रामपुर तथा रामपुर तहसील के परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला टाऊन तथा उसके उपनगर (ढल्ली, जाटोग, कसुम्पति, मशोबरा, तारादेवी एवं तुतू)।	1600 1200	2100 1500
	(च) कांगड़ा जिला : (i) बड़ा भांगल तथा छोटा भांगल के क्षेत्र	1600	2100

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		रु.14,700/- से कम वेतन	रु.14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
	<p>(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर तथा निम्नलिखित कार्यालय जो नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित हैं परंतु धर्मशाला शहर में सम्मिलित किए गए हैं – महिला आईटीआई, दारी, मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, चाइल्ड वेलफेयर एंड टाऊन एवं कंट्री प्लानिंग कार्यालय, सकोह, निचले सकोह में सीआरपीएफ कार्यालय, कांगड़ा मिल्क सप्लाय योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशॉप, साधेर, ज़ोनल मलेरिया कार्यालय, दारी, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन कार्यालय, शामनगर, टी फैक्ट्री, दारी, आई.पी.एच. उप-खंड, दान, सेटलमेंट ऑफिस, शामनगर, हिन्वा प्रोजेक्ट, शामनगर।</p> <p>पालमपुर में एचपीकेवीवी कैम्पस सहित कांगड़ा जिले का पालमपुर टाऊन तथा इसकी नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित कार्यालय परंतु जो पालमपुर टाऊन में सम्मिलित हैं – एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कैटल डेवलपमेंट ऑफिस/जर्सी फार्म, बनौरी, सेरीकल्चर ऑफिस/इंडो-जर्मन एग्रीकल्चर वर्कशॉप/एचपीपीडीब्ल्यूडी डिवीज़न, बुंदला, इलैक्ट्रीकल उप-खंड, लोहना, डी.पी.ओ. कॉरपोरेशन, बुंदला, इलैक्ट्रीकल एचईएसईई डिवीज़न, घुगर।</p>	1200	1500
	<p>(छ) मंडी जिला :</p> <p>जोगिंदरनगर तहसील की छूहार घाटी, बागरा की थुनाग तहसील में पंचायतें, छतरी, छोटधर, गुडागुसियान, गाट्टू, गरयास, जांझेली, जरयार, जोहर, कल्हानी, कलवन, खोलानल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थचधर, टाची, थाना, बिंगा-ब्लॉक धर्मपुर की पंचायतें, कमलाह, सकलाना, तन्यार तथा ताराखोला, करसोग तहसील की पंचायतें- बालीधर, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैंज, सरहन तथा तेबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें – बोही, बटवारा, धनयारा, पौड़ा-कोठी, सेरी तथा शोज़ा।</p> <p>(ज) सिरमौर जिला :</p> <p>बानी, बाखली (पच्छड़ तहसील), भरोगभेनरी (पावंता तहसील), बिड़ला (नहान तहसील), डिब्बर (पच्छड़ तहसील) तथा थाना कासोगा (नहान तहसील) और थांगिरि टैक की पंचायतें</p>	1200	1500
	<p>(झ) सोलन जिला :</p> <p>मंगल पंचायत</p> <p>(ञ) हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र जो उक्त मद (क) से (झ) में सम्मिलित नहीं हैं।</p>	1200	1500
		320	400
13.	उत्तराखंड चमौली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग तथा चम्पावत जिलों के अंतर्गत क्षेत्र।	2000	2600"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

ऐसे विनियम जिनमें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है वे, बैंक अधिकारियों के संघों के शीर्ष स्तर तथा इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिकारों के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के मध्य हस्ताक्षरित संयुक्त नोट्स के सहमत नियम एवं शर्तों के अनुसार हैं। अतः, इस प्रकार के पूर्वव्यापी प्रभाव द्वारा किसी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रदीप चौहान, महाप्रबंधक (मा. सं. वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./438/17]

नोट: मुख्य विनियम भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 17.10.1987 को प्रकाशित किए गए थे तथा तदोपरांत निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किए गए, यथा:-

1. नं. 3902 , दिनांक 5, नवंबर 1987
2. नं. 3904 , दिनांक 12, नवंबर 1988
3. नं. 3906 , दिनांक 4, नवंबर 1989
4. नं. 3908, दिनांक 7, अक्टूबर 1989
5. नं. 3910, दिनांक 5, अप्रैल 1990
6. नं. 3911, दिनांक 9, जून 1990
7. नं. 3912, दिनांक 4, मई 1991
8. नं. 3913, दिनांक 4 , अप्रैल 1992
9. नं. 3915, दिनांक 9, जनवरी 1993
10. नं. 3916, दिनांक 31, दिसंबर 1994
11. नं. 3919, दिनांक 13, अगस्त 1996
12. नं. 3921, दिनांक 30, नवंबर 1996
13. नं. 3924, दिनांक 17, अप्रैल 1999
14. नं. 3925, दिनांक 13, नवंबर 1999
15. नं. 3927, दिनांक 19, अगस्त 2000
16. नं. 3936 , दिनांक 29, सितंबर 2001
17. नं. 3940, दिनांक 06, मई 2002
18. नं. 3943, दिनांक 08 फरवरी 2006
19. नं. 3944, दिनांक 12 फरवरी 2007
20. नं. 3946, दिनांक 20, दिसंबर 2010

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
(CORPORATE OFFICE, GURUGRAM)

NOTIFICATION

Gurugram, the 24th January, 2018

No.3 950.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Regulations, 1982, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

- (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs. 3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs. 3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’

- (ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

- (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;
- (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

- (a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs. 46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs. 42000 - 1200/4 – 46800

- (b) Senior Management Grade

Scale V = Rs. 36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs. 30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 25700 - 800/5— 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs. 19400 - 700/1 - 20100 - 800/10 - 28100

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs. 14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.—Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

- (6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

(b) in sub-regulation (2),-

(j) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs. 1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

- (c) in sub-regulation (3),-
- (i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”

- (ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

- “(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;
- (iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

“(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations, -

- (i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;
- (ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;
- (iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

- “(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

- (a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) on and from the 1st day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(iv) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(v) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(vi) Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007, -

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(iv) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(v) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(vi) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (vi) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (vii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1st day of November 2002, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (viii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
 - “(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs. 290 per month or Rs. 255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
 - (4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
 - (5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.”;

(ix) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.”;

(x) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November, 2007” shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs. 680 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

(b) Hospitalization Expenses:

- (i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;
- (ii) On and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs. 700 per day Family – Rs. 525 per day</p> <p>(ii) Other charges</p> <p>At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs. 900 per day Family – Rs. 675 per day</p> <p>(ii) Other charges</p> <p>At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;</p>

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

11. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major ‘A’ Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs. 12,000
Middle Management and Junior Management	Rs. 9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
 “Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.
14. In regulation 45 of the said regulations, -
- (iv) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-
 “Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;
- (v) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-
 “(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;
- (vi) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
 “(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F. No. 5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time.”
15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-
 “Schedule to Oriental Bank of Commerce (Officers’) Service Regulations, 1982
 (See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
1.	Mizoram		
	(a) Chimgtuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei district excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram.	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	(a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(b) Udhampur District:		
	(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part b (ii).	2000	2600
	(ii) Areas up to Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District:		
	Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District :		
	All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District		
	(i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District :		
	Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(a) Chamba District		
	(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Ruppi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (i) above.	1600	2100
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District :		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.		
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghor Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	<p>(f) Kangra District:</p> <p>(i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal</p> <p>(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.</p> <p>Palampur Town of Kangra District including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.</p>	<p>1600</p> <p>1200</p>	<p>2100</p> <p>1500</p>
	<p>(g) Mandi District:</p> <p>Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.</p>	<p>1200</p> <p>1200</p>	<p>1500</p> <p>1500</p>
	<p>(h) Sirmaur District:</p> <p>Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgin Tract</p>		

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(i) Solan District : Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above	320	400
13.	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttar Kashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

PRADEEP CHAUHAN, GENERAL MANAGER (HRD)

[ADVT.-III/4/Exty./438/17]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India on 17th day of October, 1987 and subsequently amended vide following notifications, namely:-

1. No. 3902, dated the 5th day of November, 1987
2. No. 3904, dated the 12th day of November, 1988
3. No. 3906, dated the 4th day of March, 1989
4. No. 3908, dated the 7th day of October, 1989
5. No. 3910, dated the 5th day of April, 1990
6. No. 3911, dated the 9th day of June, 1990
7. No. 3912, dated the 4th day of May, 1991
8. No. 3913, dated the 4th day of April, 1992
9. No. 3915, dated the 9th day of January, 1993
10. No. 3916, dated the 31st day of December, 1994
11. No. 3919, dated the 13th day of August, 1996
12. No. 3921, dated the 30th day of November, 1996
13. No. 3924, dated the 17th day of April, 1999
14. No. 3925, dated the 13th day of November, 1999
15. No. 3927, dated the 19th day of August, 2000
16. No. 3936, dated the 29th day of September, 2001
17. No. 3940, dated the 6th day of May, 2002
18. No. 3943, dated the 8th day of February, 2006
19. No. 3944, dated the 12th day of February, 2007
20. No. 3946, dated the 20th day of December, 2010